<u>रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99</u>

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA



एस.जी.-डी.एल.-अ.-04032025-261449 SG-DL-E-04032025-261449

असाधारण EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 81] दिल्ली, सोमवार, मार्च 3, 2025/फाल्गुन 12, 1946 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 433 No. 81] DELHI, MONDAY, MARCH 3, 2025/PHALGUNA 12, 1946 [N. C. T. D. No. 433

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों के कल्याण विभाग अधिसूचना

दिल्ली, 3 मार्च, 2025

फा.सं. एफ.43(49)/2005/डीएससीएसटी/पीजी.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 की धारा 45 की उपधारा (ए) और गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 2 सितंबर 2024 को जारी एस.ओ. संख्या 3753 (ई) के साथ पिठत अनुसूचित जाित और अनुसूचित जनजाित (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के नियम 16 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल अनुसूचित जाित और अनुसूचित जनजाित (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के प्रावधानों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए राज्य स्तरीय सतर्कता और निगरानी समिति का पुनर्गठन करते हैं, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शािमल हैं:-

1. मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

-अध्यक्ष

2. गृह मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

-सदस्य

वित्त मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

-सदस्य

4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

-सदस्य

दिल्ली से निर्वाचित सभी संसद सदस्य और दिल्ली विधानसभा के सभी सदस्य.

1551 DG/2025 (1)

	जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित हों।	-सदस्य
6.	मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	-सदस्य
7.	प्रमुख सचिव, (गृह), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	-सदस्य
8.	पुलिस आयुक्त, दिल्ली	-सदस्य
9.	निदेशक/उप निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग	-सदस्य
10.	निदेशक/उप निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग	-सदस्य
11.	प्रधान सचिव/सचिव (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	
	/अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार)	-संयोजक

समिति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के प्रावधानों के कार्यान्वयन, पीड़ितों को प्रदान की गई राहत और पुनर्वास सुविधाओं और उससे संबंधित अन्य मामलों, अधिनियम के तहत मामलों के अभियोजन, अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार विभिन्न अधिकारियों/एजेंसियों की भूमिका और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा प्राप्त विभिन्न रिपोर्टों की समीक्षा करने के लिए कैलेंडर वर्ष में कम से कम दो बार, जनवरी और जुलाई के महीने में बैठक करेगी।

यह अधिसूचना इस विभाग की पूर्व अधिसूचना संख्या एफ.43(49)/2005/डीएससीएसटी/पीजी/14672-95 दिनांक 04.01.2023 के स्थान पर जारी की गई है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से ओर उनके नाम पर,

आर. के. सैनी, उप निदेशक (डीएससीएसटी)

DEPARTMENT FOR THE WELFARE OF SCs, STs, OBCs

NOTIFICATION

Delhi, the 3rd March, 2025

F. No. F.43 (49)/2005/DSCST/PG.—In exercise of powers conferred under Rule 16 of the Scheduled Castes & Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Rules, 1995, read with subsection (a) of section 45 of Government of National Territory of Delhi Act, 1991 and S.O. No. 3753(E) dated 2nd September 2024 issued by Ministry of Home Affairs, GOI, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to re-constitute the State Level Vigilance Monitoring Committee to review the implementation of the provisions of the Scheduled Castes and Scheduled tribes (Prevention of Atrocities) Act 1989, consisting of the following members: -

1.	Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi	Chairman
2.	Home Minister, Govt. of NCT of Delhi	Member
3.	Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi	Member
4.	Minister for Welfare of SC/ST/OBC/Min., Govt. of NCT of Delhi	Member
5.	All Elected Members of Parliament from Delhi and all	
	Members of Legislative Assembly of Delhi belonging to	
	The Scheduled Castes and Scheduled Tribes	Member
6.	Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi	Member
7.	Principal Secretary, (Home), Govt. of NCT of Delhi	Member
8.	Commissioner of Police, Delhi	Member
9.	Director/Dy. Director, National Commission for Scheduled Castes	Member
10.	Director/Dy. Director, National Commission for Scheduled Tribes	Member
11.	Pr. Secretary/Secretary (Department for Welfare of SC/ST/OBC), GNCTI	Convener

The Committee shall meet at least twice in a calendar year, in the month of January and July to review the implementation of the provisions of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of

Atrocities) Act 1989, relief and rehabilitation facilities provided to the victims and other matters connected therewith, prosecution of cases under the Act, role of deferent officers/agencies responsible for implementation of the provisions of the Act and various reports received by the Government of National Capital Territory of Delhi.

The notification is issued in supersession of this Department's earlier notification No.F.43 (49)/2005/DSCST/PG/14672-95 dated 04.01.2023.

By Order of and in the Name of Lt. Governor of NCT of Delhi, R. K. SAINI, Dy. Director (DSCST)